



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 1, 1990/ फाल्गुन 10, 1911

No. 5] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 1990/PHALGUNA 10, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के काम में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भारतीय खात्य नियम

अधिसूचना सं. 50

नई दिल्ली, 28 फरवरी 1990

का सं. ई. पी. 41/1/89—खात्य नियम अधिनियम, 1964
(1961 का 37) की खात्य 45 द्वारा प्रश्न याकियों पर उपयोग
करने हुए, भारतीय खात्य नियम केरलाय सरकार की पुर्वान्मालि में
भारतीय खात्य नियम (अंग्रेजी, भारतीय नियम) अधिनियम, 1967
में और गोपन बनने के लिए नियमनियमित नियम बनाये हैं, जापन—

1. (1) ये नियम, भारतीय खात्य नियम (अंग्रेजी भारतीय नियम)
संग्रहित अधिनियम, 1960 के द्वारा जापा है।

(2) ये नियम जून, 1989 के पहले दिन से लागू भाने जायेंगे।

2. भारतीय खात्य नियम (अंग्रेजी भारतीय नियम) अधिनियम, 1967 के वित्तियम 15 में जहा कहा भी, मंस्या, कोष्ठक और शब्द “8 33% (आठ दशमलव तीन तीन प्रतिशत)” आय ई. के स्थान पर मंस्या, कोष्ठक और शब्द “10% (दश प्रतिशत)” प्रक्रियावित किया जायेंगे।

व्याख्यात्मक भाग—भारतीय खात्य नियम (अंग्रेजी भारतीय नियम) अधिनियम, 1967, के अधिकारी नियम नियम अधिनियम, 1952 द्वारा गोपनित पर आश्रित है। के अधिकारी भविष्य नियम अधिनियम, 1952 के अधीन अंग्रेजी और चंदे की वर दिवाक 1-6-1989 से 8 33% से बढ़कर 10% कर दी गई है, सार्वजनिक उद्यम कार्यालय, उद्योग समाजाय, भारत मन्त्रालय ने अपने कार्यालय जापन सं. 2 (34)/ 88-वी पी है (इनपूर्व सं.) दिवाक 20-7-1989 द्वारा भी सार्वजनिक अवधि के उपकरणों का दिवाक 1-6-1989 से अंग्रेजी और चंदे का वर को 10% लक बनने के लिए दिये हैं। अतः इस विनियम को तुष्ट-ज्ञापी प्रमाण देना आवश्यक हो गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस विनियम को तुष्ट-ज्ञापी प्रमाण देने से किसी भी अक्षित जिस पर ये नियम लागू होगा उसे हिन्द को कोई प्रतिकृत प्रमाण नहीं पड़ेगा।

टिप्पणी—1. मूल अधिनियम (भारतीय खात्य नियम) [(यो पी एक) अधिनियम, 1967] दिवाक 27-5-1967 के भारतीय नामांत्र के भाग-III, खंड-1 में प्राप्तित हुआ।

३. संगोष्ठी [(सा. खा. नि.) (संपी एफ) अधिनियम 1967 का विनियम 15], दिनांक 10-8-1982 को भारतीय ग्रन्तवत्र के भाग-III बंड-१ में प्रकाशित हुआ।

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION NO. 50

New Delhi, the 28th February, 1990

F. No. EP. 11/1/89 :—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the Food Corporation of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Food Corporation of India (Contributory Provident Fund) Regulations, 1967, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Food Corporation of India (Contributory Provident Fund) Amendment Regulations, 1990.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st Day of June, 1989.

2. In regulation 15 of the Food Corporation of India (Contributory Provident Fund) Regulations, 1967, for the figures, brackets and words "8.83% (Eight decimal three-three percent)" wherever they occur, the figures, brackets and words "10%" (Ten percent)" shall be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM : The Food Corporation of India (Contributory Provident Fund) Regulations, 1967 are based on the Employees Provident Fund Act, 1952, as amended from time to time. The rate of subscription and contribution under the Employees Provident Fund Act, 1952, has now been increased from 8-1/3% to 10 percent with effect from 1-6-1989. The Bureau of Public Enterprises, Ministry of Industry, Government of India vide Office Memorandum No. 2 (34) 188-BPE (WC) dated 20-7-1989, has also issued instructions to the concerned Public Sector Undertakings to increase the rate of subscription and contribution to 10% with effect from 1-6-1989. It has, therefore, become necessary to give retrospective effect to this regulation. It is certified that by giving retrospective effect to this regulation, it shall not prejudicially affect the interest of any person to whom these regulations are applicable.

Note : 1. Original Regulations [Food Corporation of India (GPF) Regulations, 1967] published in Part-II Section 1, of the Gazette of India dated 27-5-1967.

2. Amendment [Regulation 15 of FCI (GPF) Regulations 1967] published in Part-III Section 4 in the Gazette of India dated 10-8-1982.

अधिनियम सं. 51

मं. ई.पी. 36 (2)/86—खाता नियम अधिनियम 1964 (1964 का 37) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त अधिनियम का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र गवर्नर की पूर्वानुमति में गारंटी खाता नियम (कर्मचारी-

वृद्धि) विनियम, 1971 में प्राप्ते संशोधन के लिए यार्जित खाता नियम निम्न विनियम बनाया गया है, नामसं—

1. (1) ये विनियम भारतीय खाता नियम (कर्मचारीवृद्धि) (101वां संगोष्ठी) विनियम, 1990 के जायेंगे।

(2) ये तुरंत प्रभावी होंगे।

2. भारतीय खाता नियम (कर्मचारीवृद्धि) विनियम, 1971 के वर्तमान विनियम 48 (4) को निम्नानुमति प्रतिस्थापित किया गया :—

"48 (4) —प्रधान कर्मचारी श्रेणी-I अधिकारी श्रेणी-II का जो दाये 10,000 तथा श्रेणी-III अधिकारी श्रेणी-IV का जो रु. 5,000/- मूल्य से अधिक की गंपति का लेन-देन करता है तो उसे अपने स्वामित्व वाली अधिकारी अपनी या अपने नाम में अधिकारी अपने परिवार के सदस्य के नाम में इसे ऐसी अक्षर सम्पत्ति से संबंधित किया भी लेन-देन के बारे में सभीम प्राधिकारी को शूलित करेगा। इसमें यह व्यक्तित्व है कि सभीम प्राधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्ति की जावेगी यदि किसी लेन-देन में :

(क) अधिकत का जिसके माध्यम कर्मचारी के संग्राही अवधार है, या

(ख) नियमित प्रतिष्ठित डॉलर के अनुक्रित किसी अन्य के माहौल में हो।"

क. एम. भास्तव, सचिव

NOTIFICATION NO. 51

File No. EP 36 (2)/86 :—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely :—

1. (1) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (101st amendment) Regulations 1990.

(2) They shall come into force at once.

2. The existing Regulations 48 (iv) of the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 shall be substituted as under :—

"48 (iv) : Every employee shall report to the competent authority every transaction concerning movable property owned or held by him either in his own name or in the name of a member of his family, if the value of such property exceeds Rs. 10,000/- in the case of an employee holding any Category-I or Category-II post, or Rs. 5,000/- in the case of an employee holding any Category III or Category-IV post.

Provided that the previous sanction of the competent authority shall be obtained, if any such transaction is :—

(a) with a person having official dealings with the employee; or

(b) otherwise than through a regular or reputed dealer."

K. S. BHASIN, Secy.